**Title:** Need to consider the closure of three cotton textile mills i.e. Algine Mill No.1 and 2, and Kanpur Textiles and the other 124 mills under National Textile Corporation.

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से संसद के द्वारा वर्ष १९८१ में लिये गये एक निर्णय ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के अन्तर्गत आने वाली सूती कपड़ा मिलें और ऊन मिलों के संबंध में कुछ बात कहना चाहता हूं। ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के अन्तर्गत आने वाले तीन सूती मिलें एलगिन मिल नं. वन, एलगिन मिल नं. टू और कानपुर टेक्सटाइल, इन सबका अधिग्रहण केन्द्र सरकार ने पार्लियामैंट में एक्ट बनाकर ११ जून १९८१ को किया था। उस समय केन्द्र सरकार ने इसके तीन उद्देश्य दिये थे कि मिलों को मिल मालिकों के चंगुल से बचाना और उनमें लगे श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। दूसरा, इन मिलों का आधुनिकीकरण करके वर्तमान प्रतियोगिता में भाग लेना। तीसरा, इन मिलों के द्वारा सस्ता लेकिन अच्छी क्वालिटी का कपड़ा देशवासियों को मिले। केन्द्र सरकार का दायित्व था कि वह उनमें कार्यशील पूंजी देगी, उनको प्रशासन देगी, तकनीकी ज्ञान देगी और समय समय पर उनकी देखभाल करेगी। मैं अत्यंत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा अनेक बार उठाये गये प्रश्नों के द्वारा भी केन्द्र सरकार ने बराबर इसकी अवहेलना की। अपने कर्ततव्य का पालन नहीं किया। इस नाते जो मिल अधिग्रहण के समय लाभ में चलती थी, वह घाटे में चलती चली गयीं। इन मिलों का घाटा इतना बढ़ा कि इसको बी.आई. एफ.आर. को रैफर करना पड़ा। बी.आई.एफ.आर. में केन्द्र सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने उनकी पैरवी नहीं की। उनके बंदी के आदेश हो गये तब अपील में ए.आई.एफ.आर. इलाहाबाद में गये और वहां अन्य किसी कार्यक्रम के आधार पर नहीं बल्कि पूर्व मोर्चा सरकार के इस आधार पर कि वर्तमान में केन्द्र सरकार उनमें

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please conclude. You can raise these points when the Budget is being discussed.

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : इस कारण कि केन्द्र सरकार इसमें पूंजीनिवेश करने के लिए तैयार नहीं है। ए.आई.एफ.आर. ने इनके बंदी के आदेश दिये और पूर्व मोर्चा सरकार ने उनकी बंदी का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया। यह मिलें ११ अगस्त को बंद हो जानी थी। तब से मैं प्रयासरत हूं और पूर्व प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी ने इस समस्या को समझा पर निर्णय भी टालते रहे। वर्तमान में मेरा वर्तमान सरकार मुख्य रूप से प्रधान मत्री और वस्त्र मंत्री जिनसे मैं अनेक बार मिल चुका हूं, से निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या कानपुर महानगर के लिए बहुत गंभीर है। कानपुर महानगर जो उत्तर भारत का औद्योगिक केन्द्र माना जाता है, उसका स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है। एलगिन जैसा ब्राड नाम, केलटैक्स जैसा ब्राड नेम, लालईमली जैसा ब्राड नेम और धारीवाल जैसा ब्राड नेम जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर यह मिल बंद हो जायेंगी तो कानपुर का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। दूसरी और नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अन्तर्गत आने वाली १२४ मिलों को केन्द्र सरकार बैठे बैठाए वेतन दे रही है। उनको प्रतिवर्ष ४०० करोड़ रुपये दे रही है। जब तक वह निर्णय ले तब तक एन.टी.सी. के अन्तर्गत आने वाली सूती मिलें और बी.आई.सी. के अन्तर्गत आने वाली इन तीन सूती मिलों को एक साथ लेकर निर्णय लें। इन तीन मिलों को अकेला छोड़कर बंद न करें अन्यता वहां के श्रमिक जो कि वर्तमान मिल में ५ हजार ३०० हैं, के जीवन-मरण का प्रश्न उत्पन्न हो गया है और वहां उद्योग में अशांति हो गयी है।

वहां के श्रमिकों ने ७२ घंटे तक मेरे घर को घेरे रखा था। मैं पुनः केन्द्र सरकार विशेषकर प्रधान मंत्री और वस्त्र मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी नीति को रखते हुए कोई उद्योग बंद नहीं होगा, कोई श्रमिक बेकार नहीं होगा, उसके लिए आप बजट में उनके वेतन का प्रावधान करें और एन.टी.सी. के साथ जो भी निर्णय लें उसमें इन तीन सूती मिलों का भी निर्णय लें।